



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]  
No. 112]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2005/वैशाख 9, 1927  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2005/VAISAKHA 9, 1927

### वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2005

जांच शुरूआत

**विषय :**—यूरोपीय संघ, अमरीका, चीन जन. गण. तथा ब्राजील से इथिलीन-प्रोपेलीन-असंयुक्त डाइन रबड़ (ई पी डी एम) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत

#### 1. जांच शुरूआत

फा. सं. 14/18/2004-डीजीएडी.—यतः, मै. यूनिमर्स इंडिया लि. (जिसे एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् नियम कहा गया है) के अनुसार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है जिसमें यूरोपीय संघ, अमरीका, चीन जन. गण. तथा ब्राजील के मूल के अथवा वहां से नियांतित इथिलीन-प्रोपेलीन—असंयुक्त डाइन रबड़ (ई पी डी एम) (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।

और यतः प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की उपस्थिति के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य उपस्थित हैं और वे एतद्वारा किसी कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन एवं परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की जांच प्रारंभ करते हैं।

#### 2. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद इथिलीन प्रोपेलीन - असंयुक्त डाइन रबड़ (ई पी डी एम) है। ई पी डी एम एक कृत्रिम रबड़ है और ई पी डी एम के तकनीकी विनिर्देशन मोटे तौर पर इथिलीन, प्रोपिलीन तथा डाइन घटक और/या मूनी विस्कोसिटी द्वारा शासित होते हैं। इथिलीन, प्रोपेलीन तथा डाइन घटक और/या मूनी विस्कोसिटी में भिन्नता से ई पी डी एम रबड़ के विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन किया जा

सकता है। ईपीडीएम सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 के अंतर्गत कृत्रिम रबड़ की श्रेणी के तहत चार अंकीय स्तर पर उपशीर्ष सं0 40.02 और छह अंकीय स्तर पर उप शीर्ष सं0 4002.70 के अंतर्गत वर्गीकृत है। यह भी अनुरोध किया गया है कि वस्तुओं को 38249000, 39019000 और 40021900 शीर्ष के अंतर्गत भी किलयर किया जाता है। तथापि, ये सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और जाँच के क्षेत्र पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं हैं।

ईपीडीएम रबड़ को प्राथमिक रूप से रबड़ की प्रोफाइलों आटोमोटिव टायरों और ट्यूबों केबलों, होजों और आटोमोबाइल कलपुर्जों में प्रयुक्त ढलाई की मदों में प्रयोग किया जाता है। एथिलीन, प्रोपिलीन और डाइन मात्रा और मूनी विस्कोसिटी तथा अन्य विशेषताओं में परिवर्तनों से केवल उन सामान्य गुणों में बदलाव आएगा जिनके लिए ईपीडीएम की खपत होती है। ईपीडीएम रबड़ विभिन्न ग्रेडों का हो सकता है और इसकी आपूर्ति विभिन्न रूपों में की जा सकती है। इस जाँच में सभी ग्रेडों और सभी रूपों में एथिलीन-प्रोपिलीन-नान-कानजुगेटेड डाइन रबड़ (ईपीडीएम) के सभी ग्रेड शामिल हैं। यदि हितबद्ध पक्षकार द्वारा संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों के संबंध में ग्रेड-वार आँकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं तो प्राधिकारी सामान्य मूल्य और पाठन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उचित मॉडल मिलान पद्धति अपना सकते हैं।

### 3. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

यह याचिका मै0 यूनिमर्स इंडिया लि., मुम्बई द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। इसलिए भारत में संबद्ध वस्तु का संपूर्ण उत्पादन याचिकाकर्ता द्वारा किया जाता है और वे नियमों के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग का निर्माण करते हैं।

### 4. समान वस्तु

यह नोट किया जाता है कि ईपीडीएम का उत्पादन ऐथिलीन, प्रोपिलीन तथा डाइन तत्व एवं मूनी विस्कोसिटी के आधार पर विभिन्न रूपों और ग्रेडों में किया जाता है। ईपीडीएम के विशेष ग्रेड का उपयोग प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु के विशिष्ट अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है। एक विशिष्ट वस्तु होने के कारण ग्राहक द्वारा ईपीडीएम के उपयोग हेतु अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए ईपीडीएम के उपयोग को समायोजित करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया का अनुकूलन करना अपेक्षित होता है। तथापि किसी विनिर्माता द्वारा उत्पादित ईपीडीएम की मूलभूत भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं एक जैसी रहती हैं भले ही ग्रेड में कोई भी अंतर हो और इस उत्पाद का उपयोग संयंत्र और उपकरण में कोई परिवर्तन किए बिना एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि ईपीडीएम के विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन समान कच्ची सामग्री से किया जाता है उसमें मूलभूत उत्पादन प्रौद्योगिकी उपयोग में लाई जाती है और उसे एक जैसी उत्पादन प्रक्रिया से गुजारा जाता है।

अतः यह प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं बेचे गए और संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित उत्पादों में कोई अंतर नहीं है। प्रयोक्ता उद्योगों और व्यापारियों द्वारा अन्य उद्योगों को आपूर्ति के लिए उत्पादों का सीधे आयात किया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू तथा समान आयातित उत्पादों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है। सभी आवश्यक गुणावगुणों में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित उत्पादों के समान होने के कारण नियमों के अनुसार शब्द के अर्थ के भीतर उन्हें समान वस्तु माना जाता है।

## 5. सामान्य मूल्य

कारखाना द्वार कीमतों के निर्धारण हेतु स्वीकार्य समायोजनों के पश्चात् याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर चीन जन गण को छोड़कर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के कारखाना द्वार सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है। चीन जनगण के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार उस देश को एक गैर-बाजार व्यवस्था मानकर किया गया है।

## 6. निर्यात कीमत

अलग-अलग उत्पादों की निर्यात कीमतों का आकलन डीजीसीआईएंडएस तथा अन्य गौण स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़, समुद्री बीमा, कमीशन, निर्यात के देशों/क्षेत्रों में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग तथा पत्तन प्रभार के संबंध में समायोजन किए गए हैं।

## 7. पाटन मार्जिन

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य, नियल निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे इस बात का प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

## 8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्डों के विषय में सूचना उपलब्ध कराई है। समग्र रूप में तथा उत्पाद की मांग की तुलना में आयातों की मात्रा में वृद्धि बाजार हिस्से में हानि, कीमत कटौती, कीमत हास, लाभप्रदता तथा संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में नकद हानि से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

## 9. प्रक्रिया

**क) शामिल देश/क्षेत्र:** वर्तमान जाँच में शामिल देश/क्षेत्र, यूरोपीय संघ, अमरीका, ब्राजील तथा चीन जनगण हैं।

**ख) जाँच की अवधि (पीओआई) :** वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1/10/2003 से 30/9/2004 है। तथापि क्षति जाँच की अवधि में वर्ष 2000-01 से वर्ष 2003-04 तथा जाँच की अवधि शामिल होगी।

ग) सूचना प्रस्तुत करना: संबद्ध देशों/क्षेत्रों में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों/प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी सरकारों, ज्ञात संबद्ध आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित विधि से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी,  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
भारत सरकार  
उद्योग भवन, नई दिल्ली ११००११.

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित विधि से जांच से संबंधित अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

घ) समय सीमा: वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना दैनी होगी।

ड.) अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना : नियमों के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और यदि पक्षकार की राय में ऐसी सूचना प्रस्तुत करना उचित है तो ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जाएगा और उसके कारण का एक विवरण प्रस्तुत करना होता है। किसी मामले में जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना नहीं देता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करता है या जांच में पर्याप्त बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

च) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण: नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूपान्तर रखे गए हैं।

डॉ. क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2005

## Initiation

**Subject : Initiation of antidumping investigation involving import of Ethylene-Propylene-non-conjugated Diene Rubber (EPDM) from the European Union, USA, China PR and Brazil**

**1. Initiation**

**F. No. 14/18/2004-DGAD.**—Whereas, M/s Unimers India Ltd. (hereinafter referred to as the Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as this Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred as Rules), alleging dumping of Ethylene-Propylene-non-conjugated Diene Rubber (EPDM) (hereinafter referred to as subject good), originating in or exported from the European Union, USA, China PR and Brazil (hereinafter referred to as subject countries/territories) and requested for initiation of Anti Dumping investigations for levy of Anti Dumping duties on the subject goods.

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods from the subject countries/territories, injury to the domestic industry and causal links between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**2. Product under consideration**

The product under consideration in the present petition is Ethylene-Propylene-non-conjugated Diene Rubber (EPDM). EPDM is a synthetic Rubber and technical specifications of EPDM are broadly governed by Ethylene, Propylene and Diene content and Mooney Viscosity. With the variations in Ethylene, Propylene and Diene Content and /or Mooney Viscosity, different grades of EPDM Rubber can be

1342 G1/05-2

produced. EPDM is classified under Chapter 40 of the Customs Tariff Act, 1975 under the category of synthetic rubber under sub-heading no. 40.02 at four-digit level and under no. 4002.70 at six-digit level. It has also been submitted that the goods have also been cleared under the heading 38249000, 39019000 and 40021900. However, these customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the investigation.

EPDM Rubber is primarily used in rubber profiles, automotive tyres and tubes, cables, hoses and moulded items used in the automobile parts. The changes in Ethylene, Propylene and Diene content and Mooney viscosity and other characteristics will merely modify the general property for which EPDM is consumed. EPDM Rubber can be of various grades and can be supplied in various forms. This investigation covers all grades of Ethylene-Propylene-non-conjugated Diene Rubber (EPDM) in all grades and all forms. Authority may adopt appropriate model-matching methodology for the purpose of normal value and dumping margin determination, if the interested parties provide grade-wise data with regard to the domestic sales and export sales of the subject goods.

### **3. Domestic industry and Standing**

The application has been filed by M/s Unimers India Ltd., Mumbai. The applicant is the sole producer of subject goods in India. The petitioner, therefore, accounts for complete production of subject goods in India and constitute domestic industry within the meaning of the Rules

### **4. Like article**

It is noted that EPDM is produced in various forms and grades depending upon Ethylene, Propylene and Diene content and Mooney Viscosity. Use of a particular grade of EPDM depends on the specific end use to which the goods are put to. EPDM being a specialized commodity, its usage, at the end of the customer, requires fine-tuning of the production process to accommodate the usage of EPDM made by different suppliers. However, the basic physical and chemical characteristics of EPDM produced by any manufacturer remain same irrespective of grade differentiation and the products can be used interchangeably without making any changes in the plant & equipment. It has been argued that various grades of EPDM are produced from the same general raw materials, employs the basic production technology and follow through the same production process.

It therefore, appears that there is no difference in the products produced and sold by the domestic industry and imported from subject Countries/territories. The products are being directly imported by the user industries and also by traders for supply to other industries. The consumers are using the domestic and corresponding import products interchangeably. The products produced by the domestic industry and imported from subject Countries/territories being identical in

all essential characteristics are treated as like article within the meaning of the term as per the Rules.

## 5. Normal value

The ex-works normal value of the subject goods in the subject countries, except China PR have been estimated on the basis of the information as reasonably available to the applicant domestic industry after allowing admissible adjustments to arrive at ex-works prices. Normal value in respect of China PR has been determined in terms of Annex I Para 7 and 8 of the Rules on the basis of Non-market economy presumption against that country.

## 6. Export price

The export price of individual products has been estimated on the basis of data collected from DGCI&S and other secondary sources. Adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland transportation in the Countries/territories of export, port handling and port charges have been made to arrive at the Export Price at ex-factory level.

## 7. Dumping margin

There is sufficient evidence that Normal Values of the subject goods in the subject countries/territories are significantly higher than the net export prices indicating prima-facie that the subject goods are being dumped in the Indian market by exporters from the subject countries/territories.

## 8. Injury and causal link

Petitioners have furnished information on various parameters relating to injury on account of the product under consideration. Parameters, such as increase in volume of imports both in absolute terms and in relation to the demand of the products, loss in market share, price under-selling, Price depression, profitability and cash loss in the manufacturing of subject goods, prima-facie indicate that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping.

## 9. Procedure

- a) **Countries/territories involved** The Countries/territories involved in the present investigation are the European Union, USA, Brazil and Peoples Republic of China.
- b) **Period of investigation (POI):** The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1.10.2003 to 30.9.2004. The injury

investigation period will however, cover the period 2000-01 to 2003-04 and the POI.

c) **Submission of information:** The exporters in the subject Countries/territories, their governments through their embassies/ representatives in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are requested to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

**The Designated Authority**  
**Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties**  
**Ministry of Commerce and Industry**  
**Government of India**  
**Udyog Bhavan**  
**New Delhi-110011.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

d) **Time limit:** Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than **forty (40) days** from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within **(40) forty days** from the date of the letter addressed to them.

e) **Submission of information on Non-confidential basis:** In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

f) **Inspection of public file:** Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7).

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority